नैक द्वारा ग्रेड प्राप्त

कोड क्रमांक -1203



## कार्यालय प्राचार्य

शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटापारा जिला— बलौदाबाजार—भाटापारा (छत्तीसगढ़) पिन – 493118

PH: 07726-220312

ebsite:www.gnapgcollege.in

Email: govtgnapgcollege@gmail.com

भाटापारा, दिनांक 13/05/2024

# ं//सूचना//

महाविद्यालय के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, ब्लॉक सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) के संलग्न पत्र क्रमांक 345/182/आउशि. /सम./2024 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30/04/2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें। जनविश्वास एक्ट 2023 के अन्तर्गत शोसल नंबर 32 और 42 से संबंधित इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट—2000 (21 of 2000) और एक्ट 2016 (Targeted Delivery of Financial and other subsidies, Benefits and services) में लागू की गई है। उक्त संबंध में किये गये संशोधन से अवगत होवे एवं छात्र—छात्राओं को तत्संबध में जानकारी प्रदान करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा

ब्लॉक सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in) 

प्रति.

कुलसचिव, 1. समस्त राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालय छ.ग.।

2. समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय (छ.ग.) ।

जनविश्वास एक्ट 2023 के अन्तर्गत शोसल नंबर 32 और 42 से संबंधित इन्फार्मेशन विषय:-टेक्नोलॉजी एक्ट-2000 (21 Of 2000) और आधार एक्ट 2016 (Targeted Delivery of Financial and other subsidies, Benefits and services) में लागू होने के संबंध में।

संदर्भ :-1. अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र कमांक 1218/180/सा/2024/38-1 दिनांक 18/04/2024

> 2. इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 4-32/2018/इ. सू. प्रौ / 56 दिनांक 09.01.2024

उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। कृपया उक्त पत्र में दिये बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें ।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

4. 2023

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 3 0/04/2024

पृक्रमांक /346/182/आउशि / समन्वय / 2024

प्रतिलिपि:-

अवर सचिव छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर को

संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ।

उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

## छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय,

Ho: L.201 22 4509 AD (1) DDI 1000 Seption CEHEAG Date 19 APR 2024 CHE

1 8 APR 2024]

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

--0-

क्रमांक 1218/180/सा/2024/38-1,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक

प्रति,

आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।

विषय:— जनविश्वास एक्ट 2023 के अंतर्गत सोशल नंबर 32 और 42 से संबंधित इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट,2000 (21 of 2000) और आधार एक्ट 2016 (Targeted Delivery of Financial and other subsidies, Benefits and services) में लागू होने के संबंध में।

विषयांतर्गत इलेक्टानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय से प्राप्त पत्र क्र. एफ 4-32/2018/इ.सू.प्रौ./56, दिनांक 09.01.2024 छायाप्रति मय सहपत्रों सहित नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार

(ए.आर. खान) अवर सचिव

किर्छत्तीसगढ़ शासन,उच्च शिक्षा विभाग

अति आवश्यव

15 JAN 2024

भंची क्रमांक 180 मि

छत्तीसगढ शासन इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभास

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002 (छ.ग.)

क्रमांक एफ 4-32 / 2018 / इ.सू.प्री. / 56,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 09/01/2024

प्रति,

(1) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), छत्तीसगढ़ शासन, समस्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)।

(2) समस्त कलेक्टर्स, छत्तीसगढ़।

Subject: - Gazette Notifications regarding date of appointment on the provisions of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 (18 of 2023), insofar as it relates to social numbers 32 and 42 and the entries relating thereto in the Schedule to the said Act relating to the information Technology Act, 2000 (21 of 2000) and the Aadhaar (Targeted Delilvery of Financial and Other Subsideies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016). Shall come into force

उपरोक्त विषय के संबंध में, मुख्य सचिव को सम्बोधित सांइटिस्ट 'ई', भारत सरकार, इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (साइबर लॉस एवं डाटा गवर्नेन्स ग्रुप), इलेक्ट्रानिक्स निकंतन, 6, सीजीओ काम्पलेक्स, लोधी रोड नई दिल्ली का कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक eF-no2(1)/2022-CI, दिनांक 03/11/2023 की छायाप्रति सहपत्रों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संलग्न :- यथोपरि.

१५,१५,५०५११०म (कं.कं.गीतम) अवर सचिव न्यारिप छत्तीसगढ़ शासन

इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

क्टर्यालय विष्य

पृष्ठां.क्रमांक एफ 4-32/2018/इ.सू.प्रौ./56,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 09 01 224

प्रतिलिपि:-

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यालय छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, स्टेट डाटा सेन्टर, सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संलग्न :- यथोपरि।

अवर संचिव अवर संचिव छत्तीसगढ़ शासन उ। (24) इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

fu

eF. no. 2(1)/2022-CL Government of India

Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY)

(Cyber-Laws and Data Governance group)

Electronic Niketan, 6, CGO Complex Lodhi Road, New Delhi – 110 003 Dated 03 November 2023

1 4 NOV 2023 ALS, IT

#### Office Memorandum

Subject:

Gazette Notifications regarding date of appointment on which the provisions of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 (18 of 2023), insofar as it relates to serial numbers 32 and 42 and the entries relating thereto in the Schedule to the said Act relating to the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) and the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), shall come into force

The undersigned is directed to convey that *vide* serial numbers 32 and 42 and the entries relating thereto in the Schedule to "The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 (18 of 2023)" ["Jan Vishwas Act"] enacted on 11<sup>th</sup> August, 2023, eleven (11) sections of the Information Technology Act, 2000 ("IT Act") and one (01) section of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 ("Aadhaar Act") were amended through the said Schedule to the Jan Vishwas Act. The same has been published in the Gazette Notification on 11<sup>th</sup> August, 2023, and is available at the following link:

https://egazette.gov.in/WriteReadData/2023/248047.pdf

- 2. In this connection, the undersigned is also directed to invite the attention of the addressee Ministries/Departments, State Governments/ UT Administrations, UIDAI, Controller of Certifying Authorities and CERT-In, for information and action as appropriate, to this Ministry's following notifications published through the Official Gazette on 31st October, 2023, namely,—
  - (i) Notification (Extraordinary) regarding date of appointment on which the provisions of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 (18 of 2023), insofar as it relates to serial number 32 and the entries relating thereto in the Schedule to the said Act relating to the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), shall come into force.
    - Date of appointment is 30th November, 2023.

The said Notification vide S.O. 4745(E) dated 31.10.2023 is available at the following link:

https://egazette.gov.in/WriteReadData/2023/249809.pdf

(ii) Notification (Extraordinary) regarding date of appointment on which the provisions of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 (18 of 2023), insofar as it relates

SI Sucide >

Page 1 of 20

19-11-5053

2 + NOT 2023



to serial number 42 and the entries relating thereto in the Schedule to the sarelating to the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Ben and Services) Act, 2016 (18 of 2016), shall come into force.

- Date of appointment is 30th November, 2023.

The said Notification vide S.O. 4746(E) dated 31.10.2023 is available at the following link:

https://egazette.gov.in/WriteReadData/2023/249810.pdf

(iii) Notification (Extraordinary) regarding amendments to the Information Technology (Qualification and Experience of Adjudicating Officers and Manner of Holding Enquiry) Rules, 2003 namely- the Information Technology (Qualification and Experience of Adjudicating Officers and Manner of Holding Enquiry) Amendment Rules, 2023.

The said Notification vide G.S.R. 808(E) dated 31.10.2023 is available at the following link:

https://egazette.gov.in/WriteReadData/2023/249813.pdf

Copy of the above notifications vide paragraph 2 (i) to (iii) are also enclosed herewith vide Annexures-I to III.

- 3. The amendment provisions relating to the IT Act and Aadhaar Act under the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 are enclosed herewith vide Annexure-IV. Further, the amended provisions in respect of 11 sections under the IT Act and in respect of 01 section under the Aadhaar Act as they stand after enactment of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023, are placed at Annexure-V.
- 4. This issues with the approval of the Secretary, MeitY.

(Notan Roy)

Scientist E

Tel.: 011-24301706

Email: notan.roy@meity.gov.in

To:

(1) All Secretaries to the Government of India (As per list)

- (As per list)

  (As per list)
  - (3) CEO, UIDAI, MeitY
  - (4) Controller of Certifying Authorities, MeitY
  - (5) DG, CERT-In

# Important Links for accessing the Gazette Notifications

- (i) Notification (Extraordinary) regarding date of appointment on which the provisions of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 (18 of 2023), insofar as it relates to serial number 32 and the entries relating thereto in the Schedule to the said Act relating to the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), shall come into force,
  - Date of appointment is 30th November, 2023.

The said Notification vide S.O. 4745(E) dated 31.10.2023 is available at the following link:

https://egazette.gov.in/WriteReadData/2023/249809.pdf

- (ii) Notification (Extraordinary) regarding date of appointment on which the provisions of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 (18 of 2023), insofar as it relates to serial number 42 and the entries relating thereto in the Schedule to the said Act relating to the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), shall come into force.
  - Date of appointment is 30th November, 2023.

The said Notification vide S.O. 4746(E) dated 31.10.2023 is available at the following link:

https://egazette.gov.in/WriteReadData/2023/249810.pdf

(iii) Notification (Extraordinary) regarding amendments to the Information Technology (Qualification and Experience of Adjudicating Officers and Manner of Holding Enquiry) Rules, 2003 namely- the Information Technology (Qualification and Experience of Adjudicating Officers and Manner of Holding Enquiry) Amendment Rules, 2023.

The said Notification vide G.S.R. 808(E) dated 31.10.2023 is available at the following link:

https://egazette.gov.in/WriteReadData/2023/249813.pdf

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एत.-अ.-31102023-249809 CG-DL-E-31102023-249809

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ३—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (11) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4557

नई दिल्ली, मंगलबार, सक्तूबर 31, 2023/कार्तिक 9, 1945

No. 4557]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 31, 2023/KARTIKA 9, 1945

इतैक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2023

का.जा. 4745(ल). - केन्द्रीय सरकार, जन विस्तास (उपवंधों का मंशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 18) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 30 नवंबर, 2023 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको मूचना पौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में मंबंधित उक्त अधिनियम की अनुसूची में जहाँ तक कम संख्या 32 और उसमें संबंधित प्रविष्टियों का संबंध है, उक्त अधिनियम के उपवंध प्रवृत्त होंगें। [फा.सं. 2(1)/2022-सीएल]

संदीप चटर्जी, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण : मूल अधिनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 1 में 2000 का अधिनियम संख्यांक 21, तारीख 9 जून, 2000 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पधात् 2009 का अधिनियम संख्यांक 10, तारीच 5 फ़रवरी, 2009 द्वारा संशोधित किया गया था।

6593 GE 2023



सी.जी.-डी.एल.-अ.-31102023-249810 CG-DL-E-31102023-249810

> सताबारण EXTRAORDINARY

भाग ॥—चण्ड ३—उप-चण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4558]

नर्द दिल्ली, भंगलबार, बक्तूबर 31, 2023/कार्तिक 9, 1945

No. 4558]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 31, 2023/KARTIKA 9, 1945

इलैक्ट्रानिक और सूचना पौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर,, 2023

का.आ. 4746(अ).—केन्द्रीय सरकार, जन विश्वास (उपवंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 18) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 30 नवंबर, 2023 को उस तारीख के रूप में नियन करती है जिसकों आधार (नित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रमुविधाओं और सेवाओं का सक्थित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) से संबंधित उक्त अधिनियम की अनुसूची में जहाँ तक क्रम संख्या 42 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का संबंध है, उक्त अधिनियम के उपवंध प्रवृत्त होंगें।

[फा. सं. 2(1)/2022-सीएल] मंदीप चटर्जी, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण: मूल अधिनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 1 में 2016 का अधिनियम संख्यांक 18, तारीख 26 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तल्पश्चात् 2019 का अधिनियम संख्यांक 14, तारीख 24 जुलाई, 2019 द्वारा संशोधित किया गया था

6894 GE2023

(1)

Amendment provisions relating to the Information Technology Act, 2000 and the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 under the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 (18 of 2023)

## THE SCHEDULE

<u> </u>		T	A1	Amendments
Sl. Vo.	Year	No.	Short title	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
32.	2000	21	The Information Technology Act, 2000	(***)  (A) In section 33, in sub-section (2), for the words "punished with imprisonment which may extend up to six months or a fine which may extend up to tenthousand rupees or with both", the words "liable to penalty which may extend to five lakh rupees" shall be substituted.
				<ul> <li>(B) In section 44,—</li> <li>(i) in clause (a), for the words "one lakh and fifty thousand" the words "fifteen lakh" shall be substituted;</li> <li>(ii) in clause (b), for the words "five thousand"</li> </ul>
				the words "fifty thousand" shall be substituted  (iii) in clause (c), for the words "ten thousand"  the words "one lakh" shall be substituted.
				(C) In section 45,—  (i) for the words "rules or regulations", the words "rules, regulations, directions or orders shall be substituted;
				(ii) for the words "compensation not exceeding twenty-five thousand rupees to the personaffected by such contravention or a penalty not exceeding twenty-five thousand rupees", the following shall be substituted, namely:-

"penalty not exceeding one lakh rupe in addition to compensation to the person affected by such contravention not exceeding—

- (a) ten lakh rupees, by an intermediary, company or body corporate; or
- (b) one lakh rupees, by any other person."

## (D) In section 46,-

- (i) in sub-section (1), for the words "under this Chapter", the words "under this Act" shall be substituted;
- (ii) in sub-section (IA), the words "injury or" at both the places where they occur shall be omitted.

## (E) Section 66A shall be omitted.

- (F) In section 67C, in sub-section (2), for the words "punished with an imprisonment for a term which may extend to three years and also be liable to fine", the words "liable to penalty which may extend to twenty-five lakh rupees" shall be substituted.
- (G) In section 68, in sub-section (2), for the words "on conviction to imprisonment for a term not exceeding two years or a fine not exceeding one lakh rupees or with both", the words "to penalty which may extend to twenty-five lakh rupees" shall be substituted.
- (H) In section 69B, in sub-section (4), for the words "three years and shall also be liable to fine", the words "one year or shall be liable to fine which may extend to one crore rupees, or with both" shall be substituted.
- (1) In section 70B, in sub-section (7), for the words "one lakh", the words "one crore" shall be substituted.

				(J) In section 72, for the words "punished imprisonment for a term which may extend to years, or with fine which may extend to one law rupees, or with both", the words "liable to penalty which may extend to five lakh rupees" shall be substituted.
				(K) In section 72A,—  (i) in the marginal heading, for the word "Punishment", the word "Penalty" shall be substituted;
		41		(ii) for the words "punished with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine which may extend to five lakh rupees, or with both", the words "liable to penalty which may extend to twenty-five lakh rupees" shall be substituted.
42.	2016	18	The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016	In section 41, for the words "punishable with imprisonment which may extend to one year or with a fine which may extend to ten thousand rupees or, in the case of a company, with a fine which may extend to one lakh rupees or with both", the words "liable to penalty which may extend to one lakh rupees, or in the case of a company, with penalty which may extend to ten lakh rupees" shall be substituted.

The amended provisions in respect of 11 sections under the IT Act and in respect 01 section under the Aadhaar Act as they stand after enactment of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023

Act	Sections	Earlier provisions	Amended provisions
(1)	(2)	(3)	(4)
The Information Technology Act, 2000	33	33. Surrender of licence.—(1) Every Certifying Authority whose licence is suspended or revoked shall immediately after such suspension or revocation, surrender the licence to the Controller.  (2) Where any Certifying Authority fails to surrender a licence under sub-section (1), the person in whose favour a licence is issued, shall be guilty of an offence and shall be punished with imprisonment which may extend up to six months or a fine which may extend up to ten thousand rupees or with both.	33. Surrender of licence.—(1) Every Certifying Authority whose licence is suspended or revoked shall immediately after such suspension or revocation, surrender the licence to the Controller.  (2) Where any Certifying Authority fails to surrender a licence under sub-section (1), the person in whose favour a licence is issued, shall be liable to penalty which may extend to five lakh rupees.
	44	44. Penalty for failure to furnish information, return, etc.—If any person who is required under this Act or any rules or regulations made thereunder to—	44. Penalty for failure to furnish information, return, etc.—If any person who is required under this Act or any rules or regulations made thereunder to—
		(a) furnish any document, return or report to the Controller or the Certifying Authority fails to furnish the same, he shall be liable to a penalty not exceeding one lakh and fifty thousand	(a) furnish any document, return or report to the Controller or the Certifying Authority fails to furnish the same, he shall be liable to a penalty not exceeding fifteen lakh rupees for each such failure;

- rupees for each such failure;
- (b) file any return or furnish any information, books or other documents within the time specified therefor in the regulations fails to file return or furnish the same within the time specified therefor in the regulations, he shall be liable to a penalty not exceeding five thousand rupees for every day during which such failure continues;
- (c) maintain books of account or records, fails to maintain the same, he shall be liable to a penalty not exceeding ten thousand rupees for every day during which the failure continues.
- (b) file any return or furnish information, books or on documents within the time specified therefor in the regulations fails to file return or furnish the same within the time specified therefor in the regulations, he shall be liable to a penalty not exceeding fifty thousand rupces for every day during which such failure continues;
- (c) maintain books of account or records, fails to maintain the same, he shall be liable to a penalty not exceeding one lakh rupees for every day during which the failure continues.

45. Residual penalty.—

Whoever contravenes any rules or regulations made under this Act, for the contravention of which no penalty has been separately provided, shall be liable to pay a compensation not exceeding twenty-five thousand rupees to the person affected by such contravention or a penalty not exceeding twenty-five thousand rupees.

45. Residual penalty.—Whoever contravenes any rules, regulations, directions or orders made under this Act, for the contravention of which no penalty has been separately provided, shall be liable to pay a penalty not exceeding one lakh rupees, in addition to compensation to the person affected by such contravention not exceeding—

- (a) ten lakh rupees, by an intermediary, company or body corporate, or
- (b) one lakh rupees, by any other person.

46	46. Power to adjudicate—(1) For the purpose of adjudging under this Chapter whether any person has committed a contravention of any of the provisions of this Act or of any rule, regulation, direction or order made thereunder which renders him liable to pay penalty or compensation, the Central Government shall, subject to the provisions of subsection (3), appoint any officer not below the rank of a Director to the Government of India or an equivalent officer of a State Government to be an adjudicating officer for holding an inquiry in the manner prescribed by the Central Government.  (1A) The adjudicating officer appointed under sub-section (1) shall exercise jurisdiction to adjudicate matters in which the claim for injury or damage does not exceed rupees five crore:  Provided that the jurisdiction in respect of the claim for injury or damage exceeding rupees five crores shall vest with the competent court	46. Power to adjudicate—(1) For the purpose of adjudging a under this Act whether any person has committed a contravention of any of the provisions of this Act or of any rule, regulation, direction or orde made thereunder which renders him liable to pay penalty or compensation, the Central Government shall, subject to the provisions of sub-section (3), appoint any officer not below the rank of a Director to the Government of India or an equivalent officer of a State a. Government to be an adjudicatin officer for holding an inquiry in the manner prescribed by the Central Government.  (1A) The adjudicating officer appointed under sub-section (1) shall exercise jurisdiction to adjudicate matters in which the claim for damage does not excerupees five crore:  Provided that the jurisdiction to damage exceeding rupees five crores shall vest with the competent court.
	66A. Punishment for sending offensive messages through communication service, etc.—Any person who sends, by	¥ 3 <sup>10</sup> €

a cor	s of a computer resource or amunication device,—  (a) any information that is grossly offensive or has menacing character; or	67C. Preservation and retention
rete inte	ntion of information by rmediaries.—(1) rmediary shall preserve and in such information as may pecified for such duration in such manner and format the Central Government may scribe.	of information by intermediaries.—(1) Intermediary shall preserve and retain such information as maybe specified for such duration and in such manner and format as the Central Government may prescribe.
int co su pu fo	Any intermediary who entionally or knowingly attravenes the provisions of osection (1) shall be mished with an imprisonment to a term which may extend to be years and also be liable to be.	(2) Any intermediary who intentionally or knowingly contravenes the provisions of sub-section (1) shall be liable to penalty which may extend to twenty-five lakh rupees.
di m C er ta ca sp ar co	Power of Controller to give rections.—(1) The Controller ay, by order, direct a criffying Authority or any aployee of such Authority to see such measures or cease rrying on such activities as ecified in the order if those enecessary to ensure ampliance with the provisions this Act, rules or any gulations made thereunder.	68. Power of Controller to give at directions.—(1) The Controller may, by order, direct a Certifying Authority or any employee of such Authority to take such measures or cease carrying on such activities as specified in the order if those are necessary to ensure compliance with the provisions of this Act, rules or any regulations made thereunder.  (2) Any person who
	2) Any person who intentionally or knowingly ails to comply with any order under sub-section (1) shall be	intentionally or knowingly fails to comply with any order under sub-section (1) shall be guilty of an offence and shall be liable to
of	this Act, rules or any gulations made thereunder.  2) Any person who ntentionally or knowingly fails to comply with any order	(2) Any personal intentionally to comply wisub-section (

·.)..

	guilty of an offence and be liable on conviction imprisonment for a tent exceeding two years or not exceeding one lakh or with both.	twenty-five lakh rupees a fine
	69B. Power to authorise monitor and collect traff data or information thro any computer resource for cyher security. (1) The Central Government may, enhance cyber security and identification, analysis and prevention of intrusion or spread of computer contamining the Contral Gazette, authority any agency of the Government to monitor and collect traffict data or information generated transmitted, received or store in any computer resource.  (2)  (3)  (4) Any intermediary who intentionally or knowingly contravenes the provisions of sub-section (2) shall be punished with an imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine	monitor and collect traffic date or information through any computer resource for cyber security.—(1) The Central Government may, to enhance cyber security and for identification, analysis and prevention of intrusion or spread of computer contaminant in the country, by notification in the Cofficial Gazette, authorise any agency of the Government to monitor and collect traffic data or information generated, transmitted, received or stored in any computer resource.  (2)  (3)  (4) Any intermediary who intentionally or knowingly contravenes the provisions of sub-section (2) shall be punished with an imprisonment for a term
70B	70B. Indian Computer	70B. Indian Computer
	Emergency Response Team to	Emergency Response Team to
	serve as national agency for	serve as national agency for
		Joi to as matterial agent vine
	incident response.—(1) The	incident response.—(1) The

	notification in the Official Gazette, appoint an agency of the Government to be called the Indian Computer Emergency	notification in the Official of Gazette, appoint an agency of the Government to be called the Indian Computer Emergency
	Response Team.  (2) to (5)	Response Team.  (2) to (5)
	(6) For carrying out the provisions of sub-section (4), the agency referred to in sub-section (1) may call for information and give direction to the service providers, intermediaries, data centres, body corporate and any other person.  (7) Any service provider, intermediaries, data centres, body corporate or person who fails to provide the information called for or comply with the direction under sub-section (6), shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to one lakh rupees or with both.  (8)	(6) For carrying out the provisions of sub-section (4), the agency referred to in sub-section (1) may call for information and give direction to the service providers, intermediaries, data centres, body corporate and any other person.  (7) Any service provider, intermediaries, data centres, body corporate or person who fails to provide the information called for or comply with the direction under sub-section (6), shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to one crore rupees or with both.  (8)
72	72. Penalty for breach of confidentiality and privacy.— Save as otherwise provided in this Act or any other law for the time being in force, if any person who, in pursuance of any of the powers conferred under this Act, rules or regulations made thereunder, has secured access to any electronic record,	72. Penalty for breach of confidentiality and privacy.— Save as otherwise provided in this Act or any other law for the time being in force, if any person who, in pursuance of any of the powers conferred under this Act, rules or regulations made thereunder, has secured access to any electronic record, book,

book, register, correspondence,

register, correspondence,

		information, document or other material without the consent of the person concerned discloses such electronic record, book, register, correspondence, information, document or other material to any other person shall be punished with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to one lakh rupees, or with both.	information, document or material without the consent the person concerned disclose such electronic record, book, register, correspondence, information, document or other material to any other person shall be liable to penalty which may extend to five lakh rupees.
	72A	disclosure of information in breach of lawful contract.— Save as otherwise provided in this Act or any other law for the time being in force, any person including an intermediary who, while providing services under the terms of lawful contract, has secured access to any material containing personal information about another person, with the intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or wrongful gain discloses, without the consent of the person concerned, or in breach of a lawful contract, such material to any other person, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine which may extend to five lakh rupees, or with both.	72A. Penalty for disclosure of information in breach of lawful contract.—Save as otherwise provided in this Act or any other law for the time being in force, any person including, and intermediary who, while providing services under the terms of lawful contract, has secured access to any material containing personal information about another person, with the intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or wrongful gain discloses, without the consent of the person concerned, or in breach of a lawful contract, such material to any other person, shall be liable to penalty which may extend to twenty-five lakh rupees.
, A ( I	The 41 Andhaar Targeted Delivery of Ginancial	41. Penalty for non- compliance with intimation requirements.—Whoever, being an enrolling agency or a requesting entity, fails to	41. Penalty for non-compliance with intimation requirements.—Whoever, being an enrolling agency or a requesting entity, fails to comply

and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 comply with the requirements of sub-section (2) of section 3 or sub-section (3) of section 8. shall be punishable with imprisonment which may extend to one year or with a fine which may extend to ten thousand rupees or, in the case of a company, with a fine which may extend to one lakh rupees or with both.

with the requirements of subsection (2) of section 3 or subsection (3) of section 8, shall be liable to a penalty which may extend to one lakh rupees, or in the case of a company, with penalty which may extend to ten lakh rupees.